

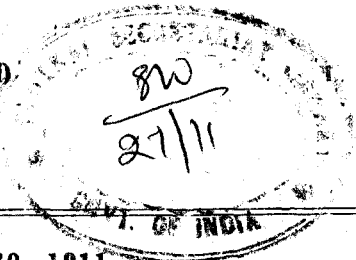


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 337]  
No. 337]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 10, 1989/ज्येष्ठ 20, 1911  
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10, 1989/JYAISTHA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
(बैंकिंग प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1989

का.आ. 434(अ) :—केन्द्रीय सरकार बैंककारी, विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता की बाबत 10 जून, 1989 को कारबार की समाप्ति से तारीख 10 अक्टूबर 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिये अधिस्थगन आदेश करता है और अधिस्थगन का कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने

या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने साधन और बाध्यताओं का निवहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा; कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या

इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

- (1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संवत् रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था की जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संवत् नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संवाय आवेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंबल रह जाती है;
- (3) तारीख 10 जून, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अनिमित्त शिकी के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या शिकी या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्ति की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य सब पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिष्ठित के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी सब पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस सब के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस सब के सबदे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में सब पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अनिमित्त की जाएगी;

(ब) तारीख 10 जून, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी रखर सम्पत्ति का विक्रय अनुसरण या उसका अन्यथा व्यवसाय नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संवाय, अर्थात् यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता की भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इनके किसी सन्तुष्टों या किसी अन्य बैंक द्वारा यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कलकत्ता को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या किए गए प्रतिवाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंबल है अतिरिक्त संवाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार यह और निवेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पूर्वोक्त संवाय करने के प्रयोजन के लिय भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलावने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश को कितनी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आवेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हफ्तवार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा निमित्त किए गए अनुरोध पर उस विषय में वास्तव लोडा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निरुपेय या परिवर्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पाबत गिरवी रखा गया है, आडमानित विलंगमित या बंधक या अन्यथा प्रसारित किया गया है :—

(1) किसी ऐसी वस्तु में जिसमें, यथास्थिति उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के सबदे पूर्व संवाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य वस्तु में, अनुबंधित अनुवातों या ऐसे अनुवातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सोनामों के अनुवात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[सं० 17/2/89 दोमो-III]

मन्त्रेश्वर झा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1989

S. O. 434 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the United Industrial Bank Limited, Calcutta for the period from the close of business on the 10th June, 1989 upto and inclusive of the 10th October, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the United Industrial Bank Limited, Calcutta shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way ;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 10th June, 1989 and realised before, on or after that date ;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred ; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar months exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred ;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 10th June, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the United Industrial Bank Limited, Calcutta by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the United Industrial Bank Limited, Calcutta shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require

the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the United Industrial Bank Limited, Calcutta.

5. The Central Government hereby further directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or

otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally ; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/2/89-BO-III]

MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.